नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 269
दि. 02.07.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

चार महानगरों में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क ध्वस्त; 9 किलो सोना, 42 किलो चांदी और करोड़ों की विदेशी मुद्रा जब्त

नई दिल्ली। देशभर में सोना तस्करी और अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अब तक की सबसे बड़ी समन्वित कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु सहित चार प्रमुख शहरों में एक साथ छापेमारी कर अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कई दिनों तक चली निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में करीब 9 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना, 42 किलोग्राम चांदी, 700 ग्राम सोने के आभूषण, 8.15 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा 26.67 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस पूरे अभियान में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हैं।

डीआरआई के अधिकारियों के अनुसार यह कोई साधारण तस्करी का मामला नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले एक सुव्यवस्थित संगठित नेटवर्क का खुलासा है, जो सोने की तस्करी, अवैध रिफाइनिंग, विदेशी मुद्रा की गैरकानूनी खरीद-फरोख्त और हवाला जैसे कई अवैध कारोबारों से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह विदेशी मूल का सोना पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते भारत में लाकर उसे अलग-अलग माध्यमों से दिल्ली और अन्य महानगरों तक पहुंचाता था। इसके बाद सोने को गलाकर उसकी पहचान बदलने और बाजार में खपाने का पूरा तंत्र विकसित किया गया था।

जांच के दौरान डीआरआई को सबसे पहले पूर्वोत्तर से दिल्ली तक संचालित तस्करी के नेटवर्क की जानकारी मिली। अधिकारियों ने 26 जून को पश्चिम बंगाल के न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन तथा बिहार के मंसी जंक्शन पर एक साथ कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से लगभग दो किलोग्राम विदेशी मूल का सोना बरामद किया गया। पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर एजेंसी दिल्ली पहुंची, जहां उसी दिन दो अन्य आरोपियों को 1.2 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से मिली जानकारी के आधार पर राजधानी के घनी आबादी वाले क्षेत्र में संचालित एक अवैध सोना गलाने की इकाई का भी पर्दाफाश हुआ। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस इकाई में तस्करी के सोने को गलाकर उसकी

पहचान मिटाई जाती थी, ताकि उसे वैध कारोबार का हिस्सा दिखाया जा सके।

डीआरआई की जांच का दायरा बढ़ने पर कोलकाता में भी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। एजेंसी ने मिजोरम के सैरांग से कोलकाता पहुंची एक महिला तस्कर को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान अधिकारियों को उसके कमरबंद में बेहद सुनियोजित तरीके से छिपाकर रखी गई 20 सोने की ईंटें मिलीं। इनका कुल वजन लगभग 3.3 किलोग्राम बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में सोने को शरीर पर छिपाकर ले जाने की यह एक बेहद संगठित और जोखिम भरी तस्करी की कोशिश थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गिरोह लगातार नए तरीकों का इस्तेमाल कर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने का प्रयास कर रहा था।

चेन्नई में की गई कार्रवाई ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया। यहां डीआरआई ने घरेलू एयर कार्गो सेवा के माध्यम से विदेशी मुद्रा की अवैध ढुलाई करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 7,58,500 अमेरिकी डॉलर और 35 लाख थाई बाहट बरामद किए, जिनकी भारतीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 8.15 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच में यह संकेत मिले हैं कि इस विदेशी मुद्रा का उपयोग विदेशों से सोना और चांदी की तस्करी के भुगतान के लिए किया जा रहा था। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क के तार किन-किन देशों और अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोहों से जुड़े हुए हैं।

बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी डीआरआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से लौटे एक यात्री को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 1.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। इसके बाद उसके घर पर छापा मारा गया, जहां से 42 किलोग्राम चांदी, लगभग 700 ग्राम सोने के आभूषण और 26.67 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। अधिकारियों का मानना है कि यह व्यक्ति तस्करी के नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य था और देश के भीतर की सप्लाई चेन संभालने में उसकी अहम भूमिका थी।

डीआरआई ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया है कि विदेशी मुद्रा की अवैध खरीद-फरोख्त, हवाला लेनदेन और सोना-चांदी की तस्करी एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विदेशी मुद्रा का उपयोग विदेशों में भुगतान करने और तस्करी के माल की खरीद के लिए किया जाता था, जबकि भारत में पहुंचने के बाद सोने और चांदी को अलग-अलग चैनलों के माध्यम से बाजार में खपाया जाता था। एजेंसी का मानना है कि यह नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय था और इसमें अनेक लोगों की भूमिका हो सकती है।

डीआरआई अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आठ आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्य, बैंक लेनदेन, मोबाइल डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की संरचना, उसके वित्तीय स्रोतों और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का पता लगाया जा सके। एजेंसी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं तथा कई अन्य राज्यों में भी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

अधिकारियों का कहना है कि सोना तस्करी केवल राजस्व हानि का मामला नहीं है, बल्कि इसका संबंध हवाला, काले धन, संगठित अपराध और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों से भी होता है। इसी कारण डीआरआई इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि देश में सक्रिय ऐसे संगठित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सघन कार्रवाई जारी रहेगी और कानून के दायरे में आने वाले सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।

नादिया में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के कार्यालय के बाहर हंगामा अंडे और सब्जियां फेंके जाने का आरोप; भाजपा पर साधा निशाना

नादिया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा के कार्यालय के बाहर उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय की ओर अंडे और सब्जियां फेंकी तथा उन्हें निशाना बनाते हुए "चोर-चोर" और "वापस जाओ" जैसे नारे लगाए। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गरमा गया और टीएमसी तथा भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।

महुआ मोइत्रा ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए दावा किया कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्हें जानबूझकर उनके कार्यालय के बाहर भेजा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी लंबे समय तक हंगामा करते रहे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर सके।

वीडियो में कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों को काले झंडे, अंडे और सब्जियां लिए हुए

नारेबाजी करते देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी लगातार सांसद के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जबकि पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान वहां मौजूद दिखाई दे रहे थे। प्रदर्शन के दौरान माहौल कुछ समय तक तनावपूर्ण बना रहा, हालांकि किसी बड़े हिंसक टकराव की सूचना सामने नहीं आई।

वीडियो में महुआ मोइत्रा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, "देखिए यहां क्या हो रहा है। पुलिस सब कुछ देख रही है। यह भाजपा की भीड़ है, जो यहां इकट्ठा हुई है। मैंने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को फोन किया है, लेकिन पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही है। सीआरपीएफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं इस क्षेत्र की निर्वाचित सांसद हूं और अपने कार्यालय के भीतर मौजूद हूं, फिर भी मेरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है।"

सांसद ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधि के कार्यालय पर इस प्रकार का हमला न केवल राजनीतिक असहिष्णुता का उदाहरण है, बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने राज्य प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए "चोर-चोर" और "वापस जाओ" जैसे नारों ने राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया। हालांकि प्रदर्शन किस विशेष मुद्दे को लेकर आयोजित किया गया था, इसे लेकर तत्काल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं भाजपा की ओर से भी इस घटना और लगाए गए आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और स्थिति पर नजर बनाए रखी। अधिकारियों के अनुसार, पूरे मामले की जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी तनाव को बढ़ा दिया है।

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर बढ़ा सियासी विवाद, आज चुनाव आयोग में होगी अहम सुनवाई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। खुद को "असली तृणमूल कांग्रेस" बताने वाले ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व वाले गुट के दावे पर केंद्रीय चुनाव आयोग गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई करेगा। इस मामले को राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि विवाद केवल संगठनात्मक नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक नाम, चुनाव चिन्ह और वैध पहचान से भी जुड़ गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस सुनवाई में आयोग की पूर्ण पीठ (फुल बेंच) कथित बागी गुट के प्रतिनिधियों का पक्ष सुनेगी। सुनवाई के लिए गुट की ओर से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका है, जो आयोग के समक्ष अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके बाद चुनाव आयोग आगे की प्रक्रिया और कानूनी परीक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश विधायक, कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में संगठनात्मक पदाधिकारी उनके साथ हैं। इसी आधार पर उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना अधिकार जताया था। उन्होंने आयोग से आग्रह किया था कि उन्हें ही पार्टी का वास्तविक प्रतिनिधि माना जाए। उस समय चुनाव आयोग ने आवेदन प्राप्त कर मामले की समीक्षा का आश्वासन दिया था।

सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन के बाद चुनाव आयोग ने इस दावे को सुनवाई योग्य मानते हुए संबंधित गुट को दोबारा बुलाया है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में आयोग की पूर्ण पीठ पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा करेगी। आयोग यह भी जांच सकता है कि गुट द्वारा पेश किए गए संगठनात्मक और विधायी समर्थन के दावे कितने तथ्यात्मक और कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं। इस बीच बागी गुट ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। कुछ दिन पहले कोलकाता के एक पांच सितारा होटल में आयोजित बैठक में इस गुट ने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस के 64 विधायक, कुछ पूर्व पार्षद और कई अन्य नेता उसमें शामिल हुए। बैठक के दौरान नई संगठनात्मक समिति के गठन की घोषणा की गई। गुट ने ममता बनर्जी के स्थान पर वरिष्ठ नेता अरूप रॉय को पार्टी का नया चेयरपर्सन घोषित करने का दावा किया, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कथित रूप से संगठन से निलंबित करने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक के बाद ऋतब्रत बनर्जी गुट ने नई समिति की सूची और अन्य संबंधित दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपते हुए स्वयं को तृणमूल कांग्रेस का वास्तविक संगठन बताया। इसी आवेदन के आधार पर आयोग ने विस्तृत चर्चा के लिए उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। आयोग का बुलावा मिलने के बाद गुट से जुड़े नेता और विधायक बुधवार को दिल्ली रवाना हो गए, ताकि सुनवाई के दौरान अपना पक्ष विस्तार से रख सकें। ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया है और उनकी ओर से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आयोग की पूर्ण पीठ के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोग सभी तथ्यों और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच करेगा तथा उचित निर्णय लेगा।

फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की आधिकारिक ओर से इस दावे को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यदि किसी राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिन्ह पर दो गुट दावा करते हैं, तो चुनाव आयोग आमतौर पर संगठनात्मक बहुमत, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के समर्थन, पार्टी संविधान और अन्य कानूनी मानकों के आधार पर मामले का परीक्षण करता है। आवश्यकता पड़ने पर आयोग दोनों पक्षों से अतिरिक्त दस्तावेज और साक्ष्य भी मांग सकता है। गुरुवार की सुनवाई को पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यह संभावना कम है कि आयोग तत्काल अंतिम फैसला सुनाए, लेकिन इस बैठक के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया, अतिरिक्त सुनवाई या दस्तावेजों की जांच को लेकर महत्वपूर्ण दिशा तय हो सकती है। ऐसे में पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और राज्य के राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर बनी हुई है।

सीवर-सेप्टिक टैंकों की मैन्युअल सफाई के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, सुरक्षा नियमों को लागू करना आवश्यक है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आजकल छोटे-बड़े सभी काम आधुनिक उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। लेकिन नालियों की सफाई के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल अभी भी खतरनाक है। परिणामस्वरूप, सेप्टिक टैंक और नालियों की सफाई के दौरान होने वाली मौतें आम बात हो गई हैं।

पिछले सप्ताह, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुंडाडा इलाके में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई। जहां एक कारखाने के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण तीन मजदूरों की जान चली गई। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर किया है। खबरों के अनुसार, मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपाय के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए

भेजा गया था। जिसके कारण यह त्रासदी हुई।

यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिल्ली समेत पूरे देश में अदालत के निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर एक विस्तृत आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सेप्टिक टैंकों और सीवरों की मैन्युअल सफाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि, हमारे गुजरात समेत कई राज्यों में समय-समय पर ऐसी दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि सुरक्षा नियमों का पालन करने के सख्त निर्देशों के बावजूद, श्रमिकों को बिना किसी सावधानी के सीवरों और सेप्टिक टैंकों में उतारा जा रहा है।

कर्मचारियों को जहरीली गैसों के बीच भेजने से पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति की जांच या उसकी शुद्धता का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इसी कारण, ऐसे हादसों में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को मुआवज़ा देने के संबंध में भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वास्तव में, केवल कागज़ पर नियम बनाने से व्यवस्था में सुधार नहीं आता। यह आवश्यक है कि इन्हें ज़मीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए और ऐसी शर्मनाक और कलंकित घटनाओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए।

राजस्थान में सामूहिक बलात्कार के आरोप में 13 वर्षीय छात्रा गिरफ्तार, 10 आरोपी गिरफ्तार

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। एक तरफ जहां पूरे देश में "बेटी को बचाओ, बेटी को शिक्षित करो" का नारा गूंज रहा है, वहीं दूसरी तरफ 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके जीवन को बर्बाद करने की एक शर्मनाक घटना सामने आई है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान के श्री गंगानगर में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ चार दिनों के भीतर लगभग एक दर्जन लोगों ने यौन उत्पीड़न किया।

शनिवार को सामने आए इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच तेज कर दी गई है।

इस संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि आरोपियों ने दुर्व्यवहार के दौरान लड़की को शराब पिलाई। लड़की को चार होटलों में प्रताड़ित किया गया।

लड़की के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसे 22 जून को जॉय इन होटल में पाया, जो इन आरोपियों का शिकार था।

संपादकीय

बुजुर्गों की सुविधा-सुरक्षा अनुकूल हों डिजिटल सेवाएं

तकनीक ने मानव जीवन की रफ्तार को अभूतपूर्व गति दी है। सुबह की चाय के डिजिटल भुगतान से लेकर हवाई टिकट और बैंकिंग तक, सब कुछ अब एक छोटी-सी स्क्रीन पर सिमट गया है। युवाओं के लिए यह सुविधा और अवसर का नया संसार है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए यही दुनिया कई बार उलझन, असुरक्षा और निर्भरता का कारण बन जाती है। अपनों से जुड़े रहने की खुशी और हर काम के डिजिटल होने की मजबूरी के बीच पुरानी पीढ़ी जिस संघर्ष से गुजर रही है, वह आज की एक बड़ी विडंबना बन गई है। स्मार्टफोन अब केवल युवाओं का उपकरण नहीं रहा। दादा-दादी वीडियो कॉल पर दूर बैठे अपने पोते-पोतियों को देखकर भावुक हो उठते हैं। व्हाट्सएप पर परिवार से जुड़े रहना, पुराने मित्रों को खोजना और यूट्यूब पर भजन सुनना उनके अकेलेपन को काफी हद तक कम करता है। लेकिन यही तकनीक कई बार उनके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। स्क्रीन पर दर्जनों एप, लगातार आने वाले संदेश, अचानक बदली हुई सेटिंग या किसी जरूरी फाइल के मिट जाने का डर उन्हें हमेशा असहज बनाए रखता है। छोटी-सी तकनीकी चूक भी उनका आत्मविश्वास डगमगा देती है। कई बुजुर्ग इस डर से स्मार्टफोन का सीमित उपयोग करते हैं और हर नए डिजिटल काम के लिए परिवार के किसी सदस्य का इंतजार करते हैं। उनकी आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होती है।

सबसे गंभीर चिंता साइबर ठगी का बढ़ता खतरा है। डिजिटल दुनिया की सीमित समझ का फायदा उठाकर अपराधी बुजुर्गों को सबसे आसान निशाना बना रहे हैं। फर्जी बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी बनकर फोन करना अब आम बात हो गई है। 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए साइबर अपराधों में ठग वीडियो कॉल के जरिए कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर वरिष्ठ नागरिकों से लाखों-करोड़ों रुपये ठग लेते हैं। केवाईसी अपडेट, पेंशन बंद होने या बैंक खाते के सत्यापन के नाम पर ओटीपी और बैंक विवरण हासिल कर जीवनभर की जमा-पूंजी साफ कर दी जाती है। आर्थिक नुकसान उन्हें गहरा मानसिक आघात भी पहुंचाता है, जिससे कई बुजुर्ग अवसाद और असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में ठगी के बाद वे खुद को दोषी मानने लगते हैं, परिवार के सामने अपनी बात रखने से हिचकिचाते हैं। स्थिति आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक संकट भी पैदा करती है। मगर वे इस डिजिटल व्यवस्था से दूर नहीं रह सकते। पेंशन, बैंकिंग, बिजली-पानी के बिल, सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार ऑनलाइन होती जा रही हैं। पहले पेंशनभोगी बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे। अब डिजिटल जीवन प्रमाण की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ उंगलियों के निशान धुंधले पड़ जाने से कई बार सत्यापन सफल नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें बार-बार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंकिंग भी अब पासबुक से आगे बढ़कर पासवर्ड, ओटीपी और मोबाइल एप पर निर्भर हो गई है। एक पासवर्ड भूल जाने का मतलब कई बार अपने ही पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना है। रेलवे टिकट, अस्पताल में पंजीकरण, गैस बुकिंग, बीमा, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसी अनेक सेवाओं में भी डिजिटल माध्यम प्रमुख हो चुका है। ऐसे में तकनीक से दूरी का अब विकल्प नहीं रह गया है।

डिजिटल बदलाव का एक सामाजिक पहलू भी है। संयुक्त परिवारों के टूटने और युवाओं के रोजगार हेतु बाहर जाने से बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। ऐसे में मोबाइल और इंटरनेट अनिवार्य जरूरत बन गए हैं। जब उनके सामने तकनीकी समस्या आती है, तब अकेलापन व असहायता का एहसास गहरा हो जाता है। जरूरी है कि डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी देखें।

निस्संदेह, तकनीक दौर में चुनौती यह है कि विकास समावेशी हो। डिजिटल सेवाओं का डिज़ाइन वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। बैंकिंग व सरकारी एप अधिक सरल हों, बड़े वित्तीय लेनदेन में अतिरिक्त मानवीय सत्यापन की व्यवस्था हो तथा साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बैंक, डाकघर, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शिविर लगाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ने संग, वे तकनीक का सुरक्षित उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल साक्षरता गांव व मोहल्ले तक पहुंचे।

जिन माता-पिता और दादा-दादी ने कभी हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्हें डिजिटल दुनिया में हमारा सहारा चाहिए। उनकी हर शंका पर झल्लाने के बजाय धैर्य से समझाना होगा कि कोई बैंक या पुलिस अधिकारी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता और न ही वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी होती है। तकनीक की सफलता तभी है, जब वह हर पीढ़ी को साथ लेकर चले। आधुनिकता का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब हमारे बुजुर्ग भी डिजिटल दुनिया में सम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ जी सकें।

तकनीक का शिकंजाः डिजिटल साक्ष्यों से अपराधियों पर कसती नकेल

> "क्राइम थ्रिलर फिल्मों में अक्सर हम देखते थे कि अपराधी बड़ी चतुराई से सबूत मिटा देता था और अंत में 'परफेक्ट मर्डर' की गुत्थी अनसुलझी रह जाती थी। तब पुलिस की सफलता उंगलियों के निशानों और चश्मदीद गवाहों पर टिकी...

क्राइम थ्रिलर फ़िल्मों में अक्सर हम देखते थे कि अपराधी बड़ी चतुराई से सबूत मिटा देता था और अंत में 'परफेक्ट मर्डर' की गुत्थी अनसुलझी रह जाती थी। तब पुलिस की सफलता उंगलियों के निशानों और चश्मदीद गवाहों पर टिकी होती थी। लेकिन आज,हर इंसान चलते-फिरते एक 'डिजिटल डेटा बैंक' बन चुका है। डिजिटल युग में 'परफेक्ट मर्डर' की धारणा अब एक मिथक मात्र है, क्योंकि तकनीकी साक्ष्य मानवीय गवाहों से अधिक विश्वसनीय साबित हुए हैं।

केतन मर्डर केस और श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसे हालिया हाई-प्रोफाइल मामलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपराधी चाहे कितने भी भौतिक सबूत मिटा ले, उसका 'डिजिटल फुटप्रिंट' - जैसे कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड , टावर लोकेशन, गूगल मैप्स हिस्ट्री और इंटरनेट सर्च क्वेरी - झूठ नहीं बोलते। यह डेटा ट्रैकिंग न केवल अभियुक्तों के 'अलबाई' (घटनास्थल पर न होने का दावा) को खारिज करती है, बल्कि अपराध के इरादे और उसकी कड़ियों को जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाती है। आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक ने अपराध जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी है, जहां 'डेटा ही सबसे बड़ा गवाह' बन गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (धारा 61 और 63) ने जांच की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। अब हत्या जैसे अपराधों की जांच केवल पोस्टमॉर्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्ष्य पर केंद्रित हो गई है। आज अपराधी चाहे कितनी भी चतुराई करे, वह अपने पीछे डेटा का एक ऐसा जाल छोड़ जाता है - जैसे कि मोबाइल लोकेशन, गूगल मैप्स, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, स्मार्ट वॉच का डेटा, व्हाट्सएप चैट्स, वाई-फाई सिग्नल, सीसीटीवी फुटेज और होम डिवाइस की वॉयस रिकॉर्डिंग, या ई-चालान में कैद कार की नंबर प्लेट - जो उसकी अपराध में संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान कानून के तहत, इन डिजिटल साक्ष्यों को अदालतों में 'प्राथमिक साक्ष्य' के रूप में पूर्ण मान्यता प्राप्त है।

भारतीय न्याय प्रणाली में डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पी.वी. (2014) और अर्जुन पंडितराव खोतकर (2020) जैसे ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की प्रमाणिकता हेतु धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये दोनों ही मामले 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता' से संबंधित हैं। भारतीय कानून ने तकनीक के युग में साक्ष्यों की सत्यता सुनिश्चित कर न्याय को सुदृढ़ तो किया है, लेकिन इसने निजता के अधिकार के समक्ष भी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। के.एस. पुट्टास्वामी (2017) का फैसला हमें आगाह करता है कि सुरक्षा के नाम पर राज्य की डिजिटल निगरानी असीमित नहीं हो सकती। कानून निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती 'डिजिटल फॉरेंसिक' के नाम पर नागरिकों की निजता और सुरक्षा के बीच एक सटीक संतुलन बनाए रखना है।

आजकल अपराध और जांच का स्वरूप पूरी तरह डिजिटल हो गया है। अपराधी 'परफेक्ट मर्डर' के लिए सबूत मिटाने हेतु डेटा हैक या डिलीट करने का सहारा लेते हैं । हालांकि, वे यह भूल जाते हैं कि डिजिटल दुनिया में 'डिलीट' किया गया डेटा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। 'डिजिटल फॉरेंसिक' और 'रिकवरी टूल्स' के जरिए पुलिस क्लाउड बैकअप, सर्वर लॉग्स और डिलीट की गई फाइलों को आसानी से पुनः प्राप्त कर सकती है। डिजिटल सर्वर पर हर गतिविधि का कोई न कोई प्रमाण हमेशा मौजूद रहता है। दरअसल, जैसे-जैसे कानून सख्त हो रहा है, अपराधी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'डार्क वेब' का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पुलिस डिजिटल साक्ष्य के सहारे आगे बढ़ रही है, वहीं अपराधी डिजिटल साक्ष्य को 'मैनीपुलेट' या 'फेक डिजिटल फुटप्रिंट' बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह साइबर-क्राइम और फोरेंसिक का एक नया युद्ध है।

आज अपराधों को रोकने के लिए व्यवस्था को 'डिजिटल-रेडी' बनाना अनिवार्य है। सबसे पहले पुलिस बल का आधुनिकीकरण करते हुए हर स्तर पर अत्याधुनिक साइबर-फोरेंसिक लैब और विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम तैयार करनी होगी। साथ ही, जजों और वकीलों को तकनीकी साक्ष्यों की बारीकियां समझने के लिए नियमित प्रशिक्षण देना जरूरी है।

साक्ष्यों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ निजी डेटा सुरक्षा और जांच के बीच एक सटीक संतुलन बनाना होगा, ताकि तकनीक का उपयोग अपराध को सुलझाने में एक मजबूत और पारदर्शी हथियार के रूप में किया जा सके। आज अपराधी चाहे जितनी चालाकी से सबूत मिटा ले, वह डिजिटल दुनिया में कोई न कोई ऐसी भूल कर देता है जो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। हालांकि, इस पूरी व्यवस्था में न्याय की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तकनीक के साथ-साथ मानवीय समझ का संतुलन भी बेहद जरूरी है।

प्रेरणा

विज्ञान की उड़ान और इंसानियत की अधूरी मंजिल

आज का युग उपलब्धियों का युग कहा जाता है। हर दिन कोई नई खोज, कोई नया आविष्कार और कोई नई तकनीक दुनिया को चौंका रही है। कभी जिस चांद को देखकर कवियों ने कल्पनाएं लिखीं, वहां आज इंसान अपने कदमों के निशान छोड़ चुका है। मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारियां चल रही हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसानों की तरह संवाद कर रही है, रोबोट अस्पतालों में ऑपरेशन कर रहे हैं और सुपर कंप्यूटर कुछ ही क्षणों में वह गणना कर लेते हैं, जिसमें पहले वर्षों लग जाते थे। मानव बुद्धि ने प्रकृति की अनेक पहेलियों को सुलझा लिया है और विज्ञान ने असंभव लगने वाले सपनों को भी वास्तविकता में बदल दिया है। लेकिन इन अद्भुत उपलब्धियों के बीच एक ऐसा प्रश्न है, जो आज भी अनुत्तरित है। यदि इंसान इतना विकसित हो गया है, तो दुनिया में शांति आज भी सबसे दुर्लभ चीज क्यों बनी हुई है?

सभ्यता का वास्तविक अर्थ केवल तकनीकी विकास नहीं होता, बल्कि वह मनुष्य के भीतर मौजूद संवेदनाओं, सहिष्णुता और आपसी विश्वास से भी तय होता है। दुर्भाग्य यह है कि विज्ञान जितनी तेज गति से आगे बढ़ा है, मानवता उतनी गति से आगे नहीं बढ़ सकी। यही कारण है कि एक ओर अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज हो रही है, तो दूसरी ओर पृथ्वी पर बारूद की गंध लगातार गहरी होती जा रही है। कहीं सीमाओं पर गोलियां चल रही हैं, कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं, कहीं निर्दोष नागरिक विस्थापित हो रहे हैं और कहीं बच्चे अपने बचपन की जगह बंकरों में रातें बिताने को मजबूर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसने आकाश को जीत लिया, वह अपने भीतर की हिंसा को नहीं जीत पाया।

हर सुबह जब अखबार खुलता है तो किसी न किसी देश में तनाव, संघर्ष या युद्ध की खबर सामने होती है। कभी किसी सीमा पर सैन्य टकराव बढ़ जाता है, कभी किसी समुद्री क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाता है और कभी किसी राजनीतिक विवाद का परिणाम हथियारों की आवाज में बदल जाता है। समाचारों की भाषा बदलती रहती है, लेकिन पीड़ा का स्वर वही रहता है। युद्ध चाहे किसी भी महाद्वीप में हो, उसकी कीमत अंततः आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। सैनिक सीमा पर जान देते हैं और आम नागरिक अपने जीवन की छोटी-छोटी खुशियां खो देते हैं।

सबसे अधिक हैरानी इस बात पर होती है कि जिन लोगों का इन संघर्षों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, वही सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। एक किसान खेत में मेहनत कर रहा होता है, लेकिन डीजल महंगा हो जाने से उसकी लागत बढ़ जाती है। एक छोटा व्यापारी दुकान चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आयात-निर्यात प्रभावित होने से सामान महंगा हो जाता है। एक मध्यमवर्गीय परिवार हर महीने अपने खर्चों का हिसाब बनाता है, लेकिन अचानक बढ़ी महंगाई उसका पूरा बजट बिगाड़ देती है। किसी दूर देश में हुआ युद्ध उसके घर की रसोई तक पहुंच जाता है। यही आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, उनका असर पूरी दुनिया के बाजारों और समाजों पर दिखाई देता है।

एक बार एक ग्राहक ने किराने की दुकान पर बढ़ी हुई कीमतों को देखकर दुकानदार से पूछा, "हर बार दाम बढ़ने का कारण क्या होता है?" दुकानदार ने सहज भाव से उत्तर दिया, "दुनिया में हालात ठीक नहीं हैं।" ग्राहक ने कहा, "लेकिन वह संकट तो हमारे देश से बहुत दूर है।" दुकानदार मुस्कराया और बोला, "अब दूरियां केवल नक्शे में बची हैं साहब, असर तो कुछ घंटों में यहां पहुंच जाता है।" यह छोटा-सा संवाद आधुनिक वैश्विक व्यवस्था की पूरी तस्वीर सामने रख देता है। आज दुनिया आर्थिक रूप से इतनी परस्पर जुड़ी हुई है कि किसी भी बड़े संघर्ष का प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है।

विज्ञान ने मनुष्य को अभूतपूर्व शक्ति दी है। लेकिन हर शक्ति अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। परमाणु ऊर्जा से शहरों को रोशन किया जा सकता है, लेकिन उसी तकनीक से पूरी सभ्यता को नष्ट भी किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा, चिकित्सा और शोध को नई दिशा दे सकती है, लेकिन यदि वही तकनीक विनाशकारी हथियारों का हिस्सा बन जाए तो उसका परिणाम भयावह हो सकता है। इसलिए समस्या विज्ञान नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करने वाले मनुष्य की सोच है। यदि सोच में करुणा होगी तो तकनीक जीवन बचाएगी, यदि सोच में स्वार्थ होगा तो वही तकनीक विनाश का साधन बन जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति की बातें बहुत होती हैं। सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं, युद्धविराम की घोषणाएं की जाती हैं और मानवाधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन घोषणाओं के कुछ ही समय बाद किसी नए क्षेत्र से हिंसा की खबर आने लगती है। ऐसा लगता है कि दुनिया के पास शांति की भाषा तो है, लेकिन शांति का साहस नहीं है। शब्दों में मानवता दिखाई देती है, लेकिन निर्णयों में अक्सर शक्ति और स्वार्थ हावी हो जाते हैं।

दुनिया की बड़ी शक्तियां भी इस विरोधाभास से अछूती नहीं हैं। वे वैश्विक मंचों पर शांति, स्थिरता और सहयोग की बात करती हैं, लेकिन रक्षा उद्योग में लगातार निवेश बढ़ाती रहती हैं। नए हथियार विकसित किए जाते हैं, सैन्य तकनीक को और अधिक घातक बनाया जाता है और हथियारों का वैश्विक व्यापार लगातार विस्तार पाता है। यह स्थिति कई बार ऐसा आभास कराती है कि युद्ध केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि एक विशाल आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा भी बन चुका है। जब शांति से अधिक लाभ संघर्ष में दिखाई देने लगे, तब मानवता की चिंता स्वाभाविक हो जाती है।

यह भी सच है कि हर युद्ध केवल आक्रमण का परिणाम नहीं होता। कई बार राष्ट्र की सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और नागरिकों की रक्षा के लिए सैन्य कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। किसी भी देश को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा बनाए रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह अधिकार तब तक ही उचित माना जाएगा, जब तक उसका उद्देश्य रक्षा हो, विनाश नहीं। जब शक्ति का उपयोग प्रभुत्व स्थापित करने या राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए होने लगे, तब सबसे बड़ी हार मानवता की होती है।

इतिहास गवाह है कि युद्धों ने कभी स्थायी समाधान नहीं दिए। उन्होंने केवल नए घाव, नई दुश्मनियां और नई पीढ़ियों के लिए नई समस्याएं पैदा की हैं। किसी शहर की टूटी हुई इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए, उनके जीवन का खालीपन कभी नहीं भरता।

भारत और सेशेल्स के बीच विकसित नए द्विपक्षीय सम्बन्धों के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ

भारत और सेशेल्स के बीच हाल के वर्षों में विकसित हुए द्विपक्षीय संबंध केवल आर्थिक और सामरिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके व्यापक अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया सेशेल्स दौरे से इस बात को और भी बल मिला है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि भारत–सेशेल्स संबंध केवल द्विपक्षीय मैत्री का उदाहरण नहीं हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, शक्ति-संतुलन, समुद्री व्यापार, जलवायु सहयोग और भारत की वैश्विक रणनीतिक भूमिका को सुदृढ़ करने वाले महत्वपूर्ण संबंध हैं। यही नहीं भविष्य में रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ब्लू इकोनॉमी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से इन संबंधों का अंतरराष्ट्रीय महत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसलिए आइए इसके वैश्विक मायने को समझने और पाठकों को समझाने की एक विनम्र कोशिश करते हैं-

पहला, हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूतः सेशेल्स हिंद महासागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है। इसलिए भारत के साथ इसकी बढ़ती साझेदारी से भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी क्षमता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को मजबूती मिलती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और प्रभाव बढ़ता है।

दूसरा, चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलनः हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते निवेश और सामरिक विस्तार के बीच सेशेल्स के साथ भारत के मजबूत संबंध क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। इससे छोटे द्वीपीय देशों के पास विविध साझेदारों के साथ सहयोग के विकल्प भी बने रहते हैं।

तीसरा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोगः दोनों देशों के बीच समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ा है। इससे पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सामूहिक समुद्री सुरक्षा को लाभ मिलता है।

चौथा, SAGAR नीति को मजबूतीः भारत की Security and Growth for All in the Region (SAGAR) नीति को सेशेल्स के साथ सहयोग से व्यावहारिक आधार मिलता है। यह नीति क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा और साझा विकास पर बल देती है।

पांचवीं, ब्लू इकोनॉमी में सहयोगः सेशेल्स की अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधनों पर आधारित है। भारत समुद्री जैव संसाधन, मत्स्य पालन, समुद्री अनुसंधान और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं।

छठा, जलवायु परिवर्तन पर साझेदारीः समुद्र-स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से छोटे द्वीपीय देशों को गंभीर खतरा है। भारत और सेशेल्स इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं और जलवायु न्याय तथा टिकाऊ विकास की वकालत करते हैं।

सातवां, हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) रणनीति में महत्वः भारत का मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण सेशेल्स जैसे साझेदार देशों के सहयोग से अधिक प्रभावी बनता है। इससे क्षेत्र में स्थिरता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

आठवां, भारत की वैश्विक कूटनीति को बलः सेशेल्स जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक देशों के साथ मजबूत संबंध भारत की वैश्विक दक्षिण (Global South) में विश्वसनीय साझेदार की छवि को मजबूत करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाते हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत–सेशेल्स संबंध केवल द्विपक्षीय मैत्री का उदाहरण नहीं हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, शक्ति-संतुलन, समुद्री व्यापार, जलवायु सहयोग और भारत की वैश्विक रणनीतिक भूमिका को सुदृढ़ करने वाले महत्वपूर्ण संबंध हैं। भविष्य में रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ब्लू इकोनॉमी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से इन संबंधों का अंतरराष्ट्रीय महत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है।

अभियान

रहस्यों, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगमः आखिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई में सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले कैसे पक जाता है?

भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में कुछ ऐसे स्थल हैं, जो केवल धार्मिक महत्व के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी अनूठी परंपराओं और रहस्यमयी व्यवस्थाओं के कारण भी पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का नाम ऐसे ही पवित्र स्थलों में सबसे प्रमुख है। यह मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर वर्ष निकलने वाली विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए पुरी पहुंचते हैं। लेकिन इस मंदिर की प्रसिद्धि केवल रथ यात्रा तक सीमित नहीं है। यहां की विशाल रसोई, महाप्रसाद की परंपरा और भोजन पकाने की अनोखी विधि भी लोगों को उतना ही आकर्षित करती है। विशेष रूप से एक बात आज भी लोगों के मन में कौतूहल पैदा करती है कि जब मिट्टी के सात बर्तनों को एक-दूसरे के ऊपर रखा जाता है, तो सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले कैसे पक जाता है? यह प्रश्न वर्षों से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी पारंपरिक मंदिर रसोइयों में गिना जाता है। यह केवल आकार में विशाल नहीं है, बल्कि अपनी व्यवस्था, अनुशासन और सदियों पुरानी परंपराओं के कारण भी अद्वितीय मानी जाती है। मंदिर परिसर के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित यह रसोई लगभग 150 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और करीब 20 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें 32 बड़े कक्ष हैं और लगभग 250 पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं। इन चूल्हों पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आधुनिक गैस, बिजली या किसी उन्नत तकनीक का उपयोग किए बिना यह व्यवस्था सदियों से सुचारु रूप से चल रही है।

प्रतिदिन यहां लगभग 600 से अधिक रसोइए और उनके सहयोगी सेवक पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं। इन रसोइयों को सामान्य कर्मचारी नहीं माना जाता, बल्कि वे पीढ़ियों से इस सेवा को धार्मिक दायित्व के रूप में निभाते आ रहे हैं। मंदिर की परंपरा के अनुसार भोजन बनाना केवल एक पाक कला नहीं, बल्कि भगवान की सेवा का माध्यम है। इसलिए प्रत्येक कार्य विशेष विधि-विधान और शुद्धता के साथ संपन्न किया जाता है।

इस रसोई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां आज भी भोजन केवल मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जाता है। चावल, दाल, सब्जियां, खिचड़ी, मिठाइयां और भगवान को अर्पित किए जाने वाले अनेक प्रकार के व्यंजन मिट्टी के पात्रों में ही बनाए जाते हैं। खाना पकाने के लिए केवल लकड़ी की आग का उपयोग होता है। आधुनिक रसोई में जहां स्टील, एल्यूमिनियम या प्रेशर कुकर का प्रयोग सामान्य बात है, वहीं जगन्नाथ मंदिर की रसोई सदियों पुरानी परंपरा को आज भी उसी स्वरूप में जीवित रखे हुए है। माना जाता है कि मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन अधिक सात्विक, सुगंधित और प्राकृतिक स्वाद वाला होता है। सबसे अधिक चर्चा जिस परंपरा की होती है, वह सात या उससे अधिक मिट्टी के बर्तनों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर भोजन पकाने की है। सामान्य विज्ञान के अनुसार आग के सबसे निकट रखा गया बर्तन पहले गर्म होना चाहिए और उसी का भोजन पहले पकना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई में पारंपरिक मान्यता यह कहती है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है, उसके बाद क्रमशः नीचे वाले बर्तनों का भोजन तैयार होता है। श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला और माता लक्ष्मी की कृपा मानते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार मंदिर की रसोई में स्वयं माता लक्ष्मी अदृश्य रूप से भोजन बनाने की व्यवस्था करती हैं, इसलिए यहां होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया साधारण नहीं मानी जाती।

हालांकि इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मिट्टी के बर्तनों की विशेष संरचना, उनके बीच बनने वाली भाप, गर्म हवा के ऊपर उठने की प्रक्रिया और बंद व्यवस्था के कारण ऊपरी बर्तनों तक अत्यधिक ताप पहुंचता है। भाप ऊपर जाकर पहले ऊपरी पात्रों को अधिक गर्म कर सकती है, जिससे वहां रखा भोजन अपेक्षाकृत जल्दी पकता है। फिर भी इस प्रक्रिया पर कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि यह विषय आज भी आस्था और जिज्ञासा दोनों का केंद्र बना हुआ है। जहां वैज्ञानिक इसे ऊष्मा और भाप के प्रवाह का परिणाम मानते हैं, वहीं श्रद्धालु इसे भगवान की दिव्य व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं।

जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि धार्मिक परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जिसे छप्पन भोग कहा जाता है। इसमें चावल, दाल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, खिचड़ी, मीठे पकवान, पिठा, खीर और अनेक पारंपरिक ओड़िया व्यंजन शामिल होते हैं। इन व्यंजनों को अत्यंत शुद्धता और धार्मिक नियमों का पालन करते हुए तैयार किया जाता है। मान्यता है कि भगवान को अर्पित होने के बाद यह भोजन केवल प्रसाद नहीं रहता, बल्कि महाप्रसाद बन जाता है, जिसे ग्रहण करना आध्यात्मिक पुण्य का कार्य माना जाता है।

महाप्रसाद बनने की प्रक्रिया भी अत्यंत विशिष्ट है। सबसे पहले भोजन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को अर्पित किया जाता है। इसके बाद यही प्रसाद मंदिर परिसर में स्थित देवी विमला को समर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी विमला को अर्पण किए बिना भोजन महाप्रसाद नहीं कहलाता। इसी प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद यह प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाता है। इस परंपरा का पालन सदियों से बिना किसी परिवर्तन के किया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद की एक और विशेषता यह है कि यहां भोजन कभी कम नहीं पड़ता और न ही आवश्यकता से अधिक बचता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन मंदिर की परंपरा के अनुसार भोजन की मात्रा ऐसी निर्धारित की जाती है कि सभी भक्तों तक प्रसाद पहुंच जाए। इसे भी भगवान की कृपा और मंदिर की अद्भुत व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि चाहे भीड़ कितनी भी अधिक क्यों न हो, महाप्रसाद की उपलब्धता बनी रहती है। इस रसोई का संचालन केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि अनुशासन, संगठन और सामूहिक सेवा का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। यहां प्रत्येक रसोइए का कार्य पहले से निर्धारित होता है। भोजन बनाने से लेकर उसे भगवान को अर्पित करने और श्रद्धालुओं तक पहुंचाने तक हर चरण निश्चित नियमों के अनुसार संपन्न होता है। सदियों से चली आ रही यह व्यवस्था आधुनिक प्रबंधन के लिए भी अध्ययन का विषय रही है।

मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक बार नए मिट्टी के पात्रों में भोजन बनाया जाता है। इससे भोजन की शुद्धता बनी रहती है और पारंपरिक स्वाद भी सुरक्षित रहता है। लकड़ी की धीमी आंच पर पकने से व्यंजनों में प्राकृतिक सुगंध आती है, जो महाप्रसाद को सामान्य भोजन से अलग पहचान देती है। यही कारण है कि अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद का स्वाद दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता।

पुरी आने वाले अधिकांश श्रद्धालु केवल दर्शन करके ही नहीं लौटते, बल्कि महाप्रसाद ग्रहण करना अपनी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानते हैं। उनके लिए यह भोजन पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद होता है। मंदिर परिसर में सभी जाति, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। यह परंपरा भारतीय संस्कृति के उस आदर्श को भी दर्शाती है, जहां भोजन समानता और भाईचारे का माध्यम बन जाता है।

आज विज्ञान और तकनीक के युग में भी जगन्नाथ मंदिर की रसोई लोगों के लिए आश्चर्य, आस्था और शोध का विषय बनी हुई है। यहां की परंपराएं यह बताती हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल प्राचीन इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन जीवित परंपराओं में भी बसती है, जिन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी श्रद्धा के साथ निभाया जा रहा है। सात बर्तनों में सबसे ऊपर रखा भोजन पहले पकने का रहस्य चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह स्पष्ट हो या न हो, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान जगन्नाथ की महिमा और माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, अनुशासन, सेवा, परंपरा और रहस्य का ऐसा अद्भुत संगम है, जो हर आने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि भारत की आध्यात्मिक विरासत केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी जीवंत है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

‘पहला सुख निरोगी काया’ और ‘प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर’ के संदेश को जीवन में उतारने की आवश्यकता है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री का स्वच्छता को सबका साझा संकल्प तथा समाज का सहज स्वभाव बनाने का आह्वान

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से ‘नमो स्वच्छता अभियान’ तथा अमृतपान अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ कराया

▸▸ 1 से 7 जुलाई तक राज्य की सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सघन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा

▸▸ स्वच्छता अब अस्पतालों की दैनिक प्रक्रिया बनेगी : स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर से ‘नमो स्वच्छता अभियान’ और ‘अमृतपान अभियान’ का राज्यव्यापी शुभारंभ कर स्वच्छता को सबका साझा संकल्प और जन-जन का सहज स्वभाव बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने जोड़ा कि स्वच्छता केवल एक सप्ताह तक सीमित रहने वाली गतिविधि नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बननी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पहला सुख निरोगी काया’ और ‘प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर’ के संदेश को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं तथा गंदगी न फैलाने और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने की सामूहिक जिम्मेदारी निभाने के लिए सभी को प्रेरणा दी।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘हर घर जल’ ‘उज्जवला योजना’, ‘आयुष्यमान भारत’ सहित अनेक पहलों से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के प्रभावी प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि सुदूरवर्ती व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नमो स्वच्छता अभियान’ अंतर्गत 1 से 7 जुलाई यानी सात दिनों के दौरान अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में पुराना फर्नीचर, आउटडेटेड मेडिकल ससांधन तथा अनावश्यक दस्तावेजों का उचित निपटान कर पूरे परिसर को स्वच्छ बनाने का कार्य किया जाएगा । उन्होंने उदाहरणों के साथ कहा कि यह अभियान केवल एक साप्ताहिक अभियान न रहकर दैनिक स्वच्छता का अभियान बने, इसके लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘अमृतपान अभियान’ बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन्म के समय से ही बच्चे को उचित पोषण और सुरक्षा मिले, इसके लिए व्यापक जनजागरूकता लाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा अच्छा स्वास्थ्य अधिक मूल्यवान है। बीमारी के समय अनुभव होने वाला तनाव स्वास्थ्य के वास्तविक महत्व को समझाता है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड को गरीब परिवारों के लिए आशीर्वाद बताते हुए कहा कि गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवा केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि मानव सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है तथा गरीब और जरूरतमंद मरीजों के आशीर्वाद से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती।

मुख्यमंत्री ने अस्पतालजनित संक्रमण की दर कम करने के लिए संक्रमण नियंत्रण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों से स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित गुजरात के निर्माण में सामूहिक प्रयासों से जुड़ने की प्रेरणा दी।

राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं दीं तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की।

‘राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस’ पर सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक ऐतिहासिक और व्यापक ‘नमो स्वच्छता अभियान’ का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया है। यह अभियान केवल एक दिन या कुछ घंटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी सात दिनों तक लगातार चलेगा और उसके बाद इसे अस्पतालों की दैनिक कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान अंतर्गत अस्पताल परिसर और कमरों में लंबे समय से पड़ी टूटी-फूटी कुर्सियां, अनुपयोगी कंप्यूटर, पुराने टेम्पो और कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंसों का सात दिनों में पूर्ण निपटान किया जाएगा तथा उस स्थान का उपयोग मरीजों की सुविधा के लिए किया जाएगा। सभी सिविल अस्पतालों तथा पीएचसी तथा सीएचसी केंद्रों में टूटी टाइलें, दरवाजे, खिड़कियां, लाइट-पंखों की फिटिंग तथा शौचालयों में लीकेज वाले नलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सफल नेतृत्व में 12 वर्षों की उपलक्ष्य में यह स्वच्छता अभियान उन्हें समर्पित एक श्रेष्ठ भेंट के समान है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने विश्वास व्यक्त किया कि ‘मन स्वच्छ, शरीर स्वच्छ, मेरा स्वास्थ्य भवन स्वच्छ’ के मंत्र के साथ गुजरात का स्वास्थ्य विभाग देशभर में अपना अग्रणी स्थान बनाए रखेगा।

इस राज्यव्यापी महाअभियान दौरान राज्य की सभी 11,935 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में परिसर से लेकर बरामदा तथा छत तक सघन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो ने स्वागत भाषण दिया, जबकि स्वास्थ्य आयुक्त (शहरी) डॉ. संध्या भुल्लर ने आभार विधि की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया सहित उपस्थित महानुभावों के करकमलों से ‘अमृतपान अभियान मार्गदर्शिका’ और ‘फ्लिप चार्ट’ का अनावरण किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य की सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता और सुव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने गांधीनगर सिविल परिसर में स्वयं सफाई कर ‘नमो स्वच्छता अभियान’ का राज्यव्यापी शुभारंभ कराया।

इस अवसर पर गांधीनगर महानगर पालिका की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, जिला पंचायत प्रमुख श्री राजेशकुमार पटेल, ग्रामीण स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. रतनकंवर गढ़वी चारण, कलेक्टर श्री रविंद्र खताले, जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैस्मीन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

गुजरात में आगामी 7 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी : प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▸▸ बिक्री के लिए 14,383 किसानों ने पंजीकरण कराया; खरीद के लिए 51 खरीद केन्द्र सुनिश्चित किए गए

▸▸ बुवाई क्षेत्र के अनुपात में प्रति किसान अधिकतम 1,500 किलोग्राम (75 मन) मूंग की खरीद की जाएगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि गुजरात में आगामी 7 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी।

उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जब भी बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है, तब किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार की ‘पीएम आशा’ योजना अंतर्गत पीएसएस के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए राज्यभर से कुल 14,383 किसानों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकृत किसानों से खरीद करने के लिए राज्य में कुल 51 खरीद केन्द्र सुनिश्चित किए गए हैं।

पंजीकरण कराने वाले किसानों को खरीद संबंधी सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। किसानों को एसएमएस प्राप्त होने के बाद उन्हें आवंटित खरीद केन्द्र पर मूंग की निर्धारित मात्रा के साथ उपस्थित रहना होगा।

वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 1,200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के आधार पर किसान के बुवाई क्षेत्र के अनुपात में की जाएगी, जिसमें प्रति किसान अधिकतम 1,500 किलोग्राम (75 मन) तक की सीमा निर्धारित रहेगी।

उन्होंने राज्य के सभी पंजीकृत किसानों से राज्य सरकार की ओर से अनुरोध किया है कि वे समय पर इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

जीएसटी कलेक्शन ने रचा नया इतिहास, जून में पहली बार 1.95 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंची वसूली

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के नौ वर्ष पूरे होने के बीच कर संग्रह ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जून 2026 में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो अब तक जून महीने का सर्वाधिक संग्रह माना जा रहा है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इसमें 13.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि लगातार बढ़ता कर संग्रह देश में मजबूत आर्थिक गतिविधियों, बेहतर कर अनुपालन, डिजिटल कर व्यवस्था की सफलता और औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार का संकेत देता है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1,71,105 करोड़ रुपये था। इसके मुकाबले इस वर्ष जून में कर संग्रह में करीब 24 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब जीएसटी प्रणाली अपने नौ वर्ष पूरे कर चुकी है और सरकार लगातार कर आधार को व्यापक बनाने तथा कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी सुधारों पर जोर दे रही है।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही भी कर संग्रह के लिहाज से उत्साहजनक रही। अप्रैल से जून 2026 के दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह 6,31,699 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 5,82,542 करोड़ रुपये था। इस प्रकार पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। लगातार तीन महीनों तक मजबूत कर संग्रह से सरकार को वित्तीय प्रबंधन और विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू कारोबार से प्राप्त सकल जीएसटी राजस्व भी जून महीने में बढ़ोतरी के साथ 1,34,774 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले वर्ष जून में यह आंकड़ा 1,26,506 करोड़ रुपये था। इससे संकेत मिलता है कि घरेलू बाजार में व्यापारिक गतिविधियां और उपभोग दोनों मजबूत बने हुए हैं। उद्योग, सेवा क्षेत्र और खुदरा कारोबार में निरंतर गतिविधियों का असर कर संग्रह पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दिया है।

जून महीने में आयातित वस्तुओं से प्राप्त जीएसटी राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आयात से होने वाला कर संग्रह 34.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ 60,038 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष जून में यह 44,600 करोड़ रुपये था। विशेषज्ञों का मानना है कि आयात में बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों और उच्च मूल्य वाले आयातित उत्पादों से सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त हुआ है।

रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह भी मजबूत बना रहा। जून 2026 में शुद्ध कर संग्रह 11.2 प्रतिशत बढ़कर 1,62,377 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं कारोबारियों को जारी किए गए जीएसटी रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। इस महीने कुल 32,436 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.1 प्रतिशत अधिक है। समय पर रिफंड जारी होने से निर्यातकों और उद्योग जगत को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है तथा व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलती है।

एक जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू की गई जीएसटी व्यवस्था को भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में गिना जाता है। इस प्रणाली ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की अवधारणा को लागू किया। इसके बाद से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी है, डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा मिला है और करदाताओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगातार बढ़ता जीएसटी संग्रह केवल कर प्रशासन की दक्षता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था में बढ़ते लेनदेन, बेहतर अनुपालन, ई-इनवॉइसिंग, डेटा विश्लेषण आधारित निगरानी और कर चोरी पर सख्त नियंत्रण का भी संकेत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग से कर संग्रह प्रणाली पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और प्रभावी हुई है।

सरकार का कहना है कि जीएसटी व्यवस्था में लगातार सुधार किए जा रहे हैं ताकि करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाया जा सके और राजस्व संग्रह को और मजबूत किया जा सके। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, डेटा इंटीग्रेशन और तकनीकी सुधारों के माध्यम से कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम जारी रहेगा।

लगातार बढ़ता जीएसटी संग्रह केंद्र और राज्यों दोनों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

स्वच्छ ऊर्जा में अडाणी ग्रीन का नया कीर्तिमान, 20 गीगावाट क्षमता पार कर बनी देश की पहली कंपनी

नई दिल्ली। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने 20 गीगावाट (जीडब्ल्यू) परिचालन क्षमता का आंकड़ा पार कर देश की पहली नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ एजीईएल ने न केवल भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान को नई गति दी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कंपनी का कहना है कि उसकी मौजूदा परियोजनाओं से अब हर वर्ष 52 अरब यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो भारत की कुल वार्षिक बिजली खपत का लगभग तीन प्रतिशत है।

कंपनी के अनुसार यह उपलब्धि सुनियोजित निवेश, आधुनिक तकनीक, बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के विकास और समयबद्ध क्रियान्वयन का परिणाम है। बीते कुछ वर्षों में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के तेजी से विस्तार के कारण एजीईएल देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बनकर उभरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी परिचालन क्षमता हासिल करना भारत के ऊर्जा परिवर्तन अभियान के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

वित्त वर्ष 2025-26 कंपनी के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इस अवधि में एजीईएल ने 5,051 मेगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी। कंपनी का दावा है कि चीन के बाहर किसी भी ऊर्जा कंपनी द्वारा एक वित्त वर्ष में जोड़ी गई यह सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। इस विस्तार में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे कंपनी का कुल परिचालन पोर्टफोलियो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया।

अडाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडाणी ने कहा कि 20 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य हासिल करना कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति, मजबूत परियोजना प्रबंधन और उत्कृष्ट क्रियान्वयन क्षमता का प्रमाण है। उनके अनुसार यह उपलब्धि केवल कंपनी की सफलता नहीं, बल्कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ती ताकत का भी परिचायक है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और एजीईएल इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी अब केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऊर्जा भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) के क्षेत्र में भी बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। एजीईएल ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 10 गीगावाट-घंटा बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने की योजना बनाई है। इसके बाद अगले पांच वर्षों में इस क्षमता को बढ़ाकर 50 गीगावाट-घंटा तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैटरी स्टोरेज क्षमता बढ़ने से सौर और पवन ऊर्जा जैसी अनियमित ऊर्जा आपूर्ति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा, जिससे बिजली ग्रिड की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी।

कंपनी ने वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र, हाइब्रिड परियोजनाएं और ऊर्जा भंडारण से जुड़े आधुनिक संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं। कंपनी का मानना है कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन और भंडारण, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से निवेश आवश्यक है।

भारत ने भी वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता विकसित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया है। ऐसे में एजीईएल जैसी कंपनियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और देश की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, आधुनिक विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा। अडाणी ग्रीन की यह उपलब्धि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है, जिसने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता और संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।

वडोदरा स्टेशन पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली का शुभारंभ,वडोदरा यार्ड री-मॉडलिंग कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल नेतृत्व में रेल परिचालन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए वडोदरा स्टेशन पर व्यापक सिग्नलिंग अपग्रेडेशन तथा यार्ड री-मॉडलिंग कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। लगभग 34 वर्ष पुरानी सीमेंस निर्मित रूट रिले इंटरलॉकिंग यानि RRI प्रणाली को हटाकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानि EI प्रणाली स्थापित की गई, जिसका सफल कमीशनिंग 01 जुलाई 2026 को किया गया। यार्ड री-मॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का यह कार्य वडोदरा स्टेशन की परिचालन क्षमता, संरक्षा, विश्वसनीयता तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य स्वीकृत 70 दिवसीय ट्रैफिक वर्किंग ऑर्डर (TWO) के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से सम्पन्न किया जा रहा है। 16 मई से 29 जून 2026 तक 45 दिनों की प्री-ट्रैफिक वर्किंग अवधि में कुल 209 घंटे 55 मिनट के एकीकृत ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लेकर विभिन्न आधारभूत कार्य पूरे किए गए। इसके पश्चात 30 जून से 01 जुलाई 2026 तक निर्धारित नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य मात्र 23 घंटे 55 मिनट में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, जबकि इसके लिए 24 घंटे का समय निर्धारित था। इस अवधि में केवल 5 घंटे 46 मिनट का ट्रैफिक ब्लॉक लेकर 147 ट्रेनों (70 अप एवं 77 डाउन) का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया।

यार्ड री-मॉडलिंग के अंतर्गत परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग को हटाकर यार्ड का ट्रैक विन्यास आधुनिक बनाया जा रहा है। डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग के कारण लागू 10 किमी/घंटा की स्थायी गति सीमा (Permanent Speed Restriction) हटाकर लाइन संख्या 6 एवं 7 पर अनुमेय गति 30 किमी/घंटा कर दी गई है। इससे यार्ड में ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम, तेज एवं सुरक्षित होगी। डाउन दिशा से आने वाली ट्रेनों का प्लेटफॉर्म संख्या 6 एवं 7 पर शीघ्र प्रवेश संभव होगा, जिससे ट्रेन डिटेंशन में कमी आएगी तथा परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके साथ ही स्टेशन पर नया स्टेशन मास्टर कार्यालय, उपकरण कक्ष एवं स्टोर भी स्थापित किए गए हैं।

वडोदरा स्टेशन पर यार्ड री-मॉडलिंग के तहत वडोदरा यार्ड में 10 पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग (P&C) हटाए गए, 12 स्थानों पर ट्रैक लेआउट में सुधार किया गया तथा 13 नए पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग स्थापित किए गए। लगभग 1.5 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाकर लाइन संख्या 6 एवं 7 को डाउन मेन लाइन तथा सी केबिन को अप गुड्स मेन लाइन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त 10 WCMS, 22 टर्नआउट का नवीनीकरण (TTR/TSR), 15 थिक वेब स्विच (TWS) की स्थापना तथा 22 पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग एवं 1.5 किलोमीटर ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग का कार्य भी सम्पन्न किया गया।

सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के अंतर्गत वर्ष 1992 में स्थापित 228 रूटों वाली RRI प्रणाली को प्रतिस्थापित कर 189 रूट एवं 10 स्लॉट वाली अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) प्रणाली स्थापित की गई है। नई प्रणाली में 65 डीसी ट्रैक सर्किटों के स्थान पर 66 ड्यूल MSDAC इकाइयों की स्थापना की

राज्य में मेहसाणा जिला पंचायत की सर्वप्रथम नूतन पहल : ‘जिला पंचायत आपके द्वार’ कार्यक्रम का शक्तिपीठ बहुचराजी से शुभारंभ

▸▸ जनता की समस्याओं के मौके पर ही समाधान के लिए प्रशासन सक्रिय; सड़क-मार्ग, पानी और पंचायत से जुड़े लंबित मुद्दों पर लिए गए त्वरित निर्णय

▸▸ प्रशासनिक प्रक्रिया को वेग देने के लिए तहसील स्तर पर मस्टर मैंटेन कर हर महीने रिव्यू लिया जाएगा : जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल

गांधीनगर : ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी लंबित तथा जनहित से जुड़ी समस्याओं की प्रस्तुति के लिए जिला मुख्यालय तक न आना पड़े; इस उद्देश्य से मेहसाणा जिला पंचायत द्वारा राज्य में पहली बार ‘जिला पंचायत आपके द्वार’ कार्यक्रम की नूतन पहल की गई है। मेहसाणा जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल के मार्गदर्शन में इस अभियान का शुभारंभ बुधवार को सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ बहुचराजी से किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन सीधे ही जनता के द्वार पहुँचा, जिसमें पहली बार आवेदकों को खुले मन से अपनी मूलभूत समस्याएँ प्रस्तुत करने के लिए एक सटीक मंच प्रदान किया गया। बहुचराजी के अन्नपूर्णा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बहुचराजी तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर सड़क-मार्ग, पेयजल, बोरवेल, ग्राम पंचायत में पटवारी की उपस्थिति तथा नवीन ग्राम पंचायत भवन जैसे मूलभूत विषयों से संबंधित समस्याएँ प्रस्तुत कीं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल ने प्रत्येक प्रस्तुति को अत्यंत गंभीरता से सुना तथा स्थल पर उपस्थित सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों से इन समस्याओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयसीमा में समाधान किया जाए तथा नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो; इसका ध्यान रखा जाए।

इस कार्यक्रम के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों पर विस्तृत चर्चाएँ हुईं, जिसमें शंखलपुरे-कालरी बाईपास पर नहर के कारण रुके हुए 200 मीटर सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने, डोडीवाडा-आदीवाडा से खांभेल चौकडी तक की क्षतिग्रस्त सड़क को नई एवं चौड़ी बनाने और कनोडा-रणेला सड़क के अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा करने संबंधी प्रस्तुतियाँ की गईं। इसके अतिरिक्त; रणेला ग्राम पंचायत में स्थायी पटवारी की नियुक्ति करने, नया पंचायत घर बनाने तथा आकबा-बरियफ रोड का नया निर्माण कराने जैसी मांगों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

ग्रामीणों द्वारा सदुथला गाँव में पेयजल के लिए नया बोरवेल बनाने तथा रातेज-राजपुरा-देथली रेलवे अंडरपास के कारण लंबे समय से बंद पड़ी एसटी बस सेवा को पुनः प्रारंभ कराने के लिए भी प्रबल प्रस्तुति की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासनिक सेवाएँ अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक सरलता से पहुँचें तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो; यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक तहसील में चिटनीश द्वारा एक अलग मास्टर लागू किया जाएगा, जिसमें प्रस्तुत की गई समस्याओं का पंजीकरण कर उनका फॉलो-अप लिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा हर महीने इन समस्याओं की समीक्षा की जाएगी तथा जो विषय राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित होंगे, उन्हें उच्च स्तर पर प्रस्तुत कर शीघ्र समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में बहुचराजी के टीडीओ श्री जे. जे. चौधरी ने इस नूतन पहल की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सभी को इसकी जानकारी दी। लोक दरबार के साथ-साथ इस अवसर पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रमाणपत्रों का भी वितरण किया गया, जिसमें आयुष्मान कार्ड, आय प्रमाणपत्र तथा जाति प्रमाणपत्र के लाभार्थियों को अधिकारियों के करकमलों से प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

विकसित गुजरात@2047 के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की एक निर्णायक और परिवर्तनकारी पहल

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप का अनावरण किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप राज्य की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव है

▸▸ सभी के समन्वित और निष्ठापूर्ण प्रयासों से विकसित गुजरात का निर्माण अवश्य ही होगा

▸▸ गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी) और सामान्य प्रशासन विभाग के आयोजन प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप के अनावरण अवसर पर वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रेरक उपस्थिति

▸▸ सरकार के पास संसाधनों या पैसों की कोई कमी नहीं है : अब केवल सच्ची निष्ठा, मजबूत निगरानी और समय पर समीक्षा की ही जरूरत : मुख्य सचिव श्री एम.के. दास

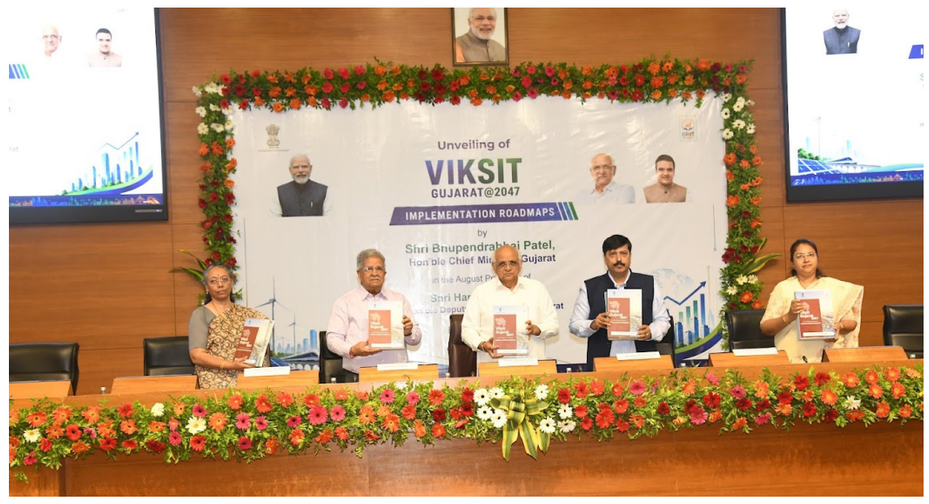

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित गुजरात @ 2047 कार्यान्वयन रोडमैप के अनावरण के जरिए विजन से ऑन ग्राउंड एक्जीक्यूशन (जमीनी स्तर पर लागू करना) की ओर राज्य सरकार की एक निर्णायक और परिवर्तनकारी पहल की है।

मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को गांधीनगर में जारी किया गया यह रोडमैप गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) और सामान्य प्रशासन विभाग के आयोजन प्रभाग की ओर से संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया सहित कई वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किए गए विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप को राज्य की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र दिया है, जिसमें उनकी मंशा राज्यों की भी सक्रिय भागीदारी से समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

उन्होंने साफ कहा कि रोडमैप यह स्पष्ट करता है कि क्या करने की आवश्यकता है, किसे करना है और किस समयसीमा में करना है, जिससे एक केंद्रित (फोकस्ड) और जवाबदेह शासन सुनिश्चित होता है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य के बजाय परिणामों पर जोर देते हुए कहा कि यह कार्यान्वयन रोडमैप अंततः नागरिकों के लिए बेहतर आजीविका, मजबूत बुनियादी ढांचा, समावेशी और टिकाऊ विकास के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें शासन में गुणवत्ता की प्रधानमंत्री की हिमायत को जीआरआईटी-ग्रिट की स्थापना और उसके द्वारा तैयार किए गए दीर्घकालिक रणनीतिक विजन वाले रोडमैप के कार्यान्वयन के जरिए चरितार्थ करना है, जिसका लक्ष्य गुजरात को प्रतिस्पर्धी, समावेशी, टिकाऊ और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन स्टेट के रूप में स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम आदमी की खुशहाली और उसके आर्थिक आधार को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 'अनिंग वेल, लिविंग वेल' यानी बेहतर कमाई, बेहतर जीवन की जो अवधारणा दी है, उसे पूरा करने में ग्रिट के इस रोडमैप का कार्यान्वयन पथप्रदर्शक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हमने विकसित गुजरात 2047 कार्यान्वयन रोडमैप में जो माइक्रो प्लानिंग की है, उसे कार्ययोजना के माध्यम से लागू करने तथा समन्वित और निष्ठापूर्ण साझा प्रयासों से विकसित गुजरात अवश्य ही बनेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12 वर्षों के सुशासन में विकास के जो दृष्टिकोण अपनाए हैं, उसे आगे बढ़ाने से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना है। गुजरात ने विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी रहने का जो संकल्प किया है, उसे बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत रहना होगा।

इस उद्देश्य के लिए, मुख्यमंत्री ने हमेशा बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और 'चलता है' वाली मानसिकता को दूर करके 100 फीसदी शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्यों की बात को केंद्र में रखकर गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की सीख भी दी।

मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने कहा कि आज भारत अभाव से प्रभाव की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए के लिए विकसित गुजरात का रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो असंभव न हों, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़े। सौभाग्य से गुजरात सरकार के पास संसाधन या बजट-धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब केवल सच्ची निष्ठा, मजबूत निगरानी और समय पर समीक्षा की ही जरूरत है।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि विकास की इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) तक, सभी अधिकारियों को और भी सक्रिय होना पड़ेगा। यदि किसी विभाग को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई वित्तीय सहायता, नीति में बदलाव या नए निर्णयों की जरूरत हो, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बंदरगाह और परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में केपीआई के अनुसार संतुलित विकास ही हमारी प्राथमिकता है।

जीआरआईटी की सीईओ सुश्री एस. अपर्णा ने 'विकसित गुजरात @2047 कार्यान्वयन रोडमैप' पर विस्तृत प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जनवरी, 2024 में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, जिसमें राज्य के सभी 26 विभागों के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2047 तक गुजरात का सकल घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस रोडमैप में लिविंग वेल और अर्निंग वेल के मंत्र को साकार करने के लिए मुख्य 11 थीम (विषय), 120 मैक्रो गोल (व्यापक लक्ष्य) तथा 55 की थ्रस्ट एरिया (प्रमुख फोकस क्षेत्र) निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि विकसित गुजरात @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्यों के आधार पर ही यह रोडमैप तैयार किया गया है। जिसमें राज्य के 26 विभागों के लिए लगभग 900 स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं। विकसित गुजरात @2047 डैशबोर्ड में शिक्षा, कृषि, पर्यटन और जलापूर्ति विभाग में मौजूदा स्थिति और भविष्य के आयोजन के बारे में रोडमैप को साकार करने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव (आयोजन) श्री आद्रा अग्रवाल ने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने 'विकसित भारत@2047' की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। इसी विजन के अनुरूप गुजरात सरकार ने भी वर्ष 2047 तक वैश्विक स्तर पर समृद्ध, प्रतिस्पर्धी, सर्वसमावेशी, टिकाऊ और इनोवेशन-आधारित राज्य बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कार्यों की सटीक समीक्षा के लिए गांधीनगर स्थित 'ग्रिट' कार्यालय में एक अत्याधुनिक 'स्ट्रैटेजी रूम' तैयार किया गया है, जिसमें डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंतर में 'ग्रिट' की जॉइंट सीईओ श्री स्तुति चारण ने आभार व्यक्त किया।

बारिश की फुहारों में भी निखरे दुल्हन का रूप, मानसून वेडिंग के लिए अपनाएं स्मार्ट ब्यूटी और स्टाइल टिप्स

मानसून का मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी हवाएं और रिमझिम फुहारों का ऐसा सुहाना एहसास लेकर आता है, जो किसी भी शादी को और अधिक यादगार बना देता है। बारिश की बूंदों के बीच सजा विवाह समारोह अपने आप में एक अलग ही रोमांस और खूबसूरती समेटे होता है। यही कारण है कि आजकल कई जोड़े मानसून वेडिंग को प्राथमिकता देने लगे हैं। हालांकि यह मौसम जितना खूबसूरत है, उतनी ही सावधानी भी मांगता है। उमस, बारिश, नमी और फिसलन जैसी परिस्थितियां दुल्हन के मेकअप, हेयरस्टाइल, पहनावे और पूरे लुक को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यदि आपकी शादी बारिश के मौसम में होने वाली है, तो केवल सुंदर परिधान चुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौसम के अनुरूप पूरी तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है।

दुल्हन की खूबसूरती केवल शादी वाले दिन किए गए मेकअप से नहीं निखरती, बल्कि उसकी शुरुआत कई सप्ताह पहले से त्वचा और बालों की नियमित देखभाल से होती है। मानसून के दौरान वातावरण में बढ़ी हुई नमी के कारण त्वचा पर अतिरिक्त तेल, पसीना और धूल जमा होने लगती है, जिससे चेहरा बेजान और थका हुआ दिखाई दे सकता है। खासकर तैलीय और मिश्रित त्वचा वाली महिलाओं को इस मौसम में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। नियमित क्लीनिंग, टोनिंग और हल्के ऑयल-फ्री मॉइस्चराइज़र का उपयोग त्वचा को संतुलित बनाए रखता है और मेकअप के लिए बेहतर आधार तैयार करता है।

बारिश के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण बात है वाटरप्रूफ मेकअप का चयन। सामान्य मेकअप उत्पाद नमी, पसीने या बारिश की हल्की बूंदों के संपर्क में आते ही फैल सकते हैं, जिससे पूरा लुक बिगड़ सकता है। इसलिए वाटरप्रूफ फाउंडेशन, कंसीलर, मस्कारा, आईलाइनर और लिप कलर का उपयोग करना बेहतर रहता है। शादी से कुछ दिन पहले मेकअप ट्रायल अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कौन-से उत्पाद आपकी त्वचा पर लंबे समय तक टिकते हैं और मौसम का प्रभाव कितना पड़ता है। यदि संभव हो तो ट्रायल के दौरान चेहरे पर हल्के पानी के छींटे डालकर भी उसकी टिकाऊ क्षमता की जांच की जा सकती है।

मॉनसून में मेकअप को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर बेहद उपयोगी साबित होता है। यह अतिरिक्त नमी और तेल को सोखकर चेहरे को मैट फिनिश देता है तथा मेकअप को बहने से बचाता है। क्रीम आधारित ब्लश और आई शैडो की बजाय पाउडर आधारित उत्पाद अधिक उपयुक्त रहते हैं क्योंकि वे अधिक समय तक टिके रहते हैं और उमस में जल्दी खराब नहीं होते।

आंखों का मेकअप करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि काजल या आईलाइनर का उपयोग करना है तो केवल वाटरप्रूफ उत्पाद ही चुनें। सामान्य काजल बारिश या पसीने की वजह से फैल सकता है, जिससे आंखों के आसपास कालापन दिखाई देने लगता है। बहुत भारी या गहरे रंग का आई मेकअप करने के बजाय हल्का और प्राकृतिक लुक अधिक आकर्षक लगता है। इसी प्रकार बिंदी के लिए वाटरप्रूफ लिक्विड बिंदी या अच्छी गुणवत्ता वाली स्टिकर, कुंदन अथवा स्टोन वाली बिंदी बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि ये नमी में भी अपनी जगह पर बनी रहती हैं।

मानसून में हेयरस्टाइल का चुनाव भी सोच-समझकर करना चाहिए। इस मौसम में खुले बाल जल्दी फ्रिज़ी हो जाते हैं और उनकी चमक कम हो सकती है। इसलिए साफ-सुथरा बन, लो बन, ब्रेडेड बन, फिशटेल चोटी या स्टाइलिश पोनीटेल जैसे हेयरस्टाइल अधिक सुविधाजनक रहते हैं। हल्के फूलों या आकर्षक हेयर एक्सेसरीज़ के साथ इन्हें और खूबसूरत बनाया जा सकता है। यदि बालों में फ्रिज़ की समस्या रहती है तो शादी से पहले हेयर स्पा या डीप कंडीशनिंग करवाना लाभदायक रहता है। एंटी-फ्रिज़ सीरम का उपयोग भी बालों को व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करता है। बारिश के मौसम में परिधान का चयन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। बहुत भारी, मोटे या अत्यधिक कढ़ाई वाले वस्त्र न केवल वजन बढ़ाते हैं, बल्कि भीगने पर असुविधाजनक भी हो जाते हैं। ऑर्गेंजा, शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप, साटन और हल्के सिल्क जैसे फैब्रिक मानसून के लिए बेहतर माने जाते हैं। ये कपड़े अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और लंबे समय तक पहनने में आरामदायक रहते हैं। यदि लहंगा पहन रही हैं तो उसकी लंबाई इतनी रखें कि वह जमीन पर अधिक न घिसटे, जिससे कीचड़ और गंदगी से बचाव हो सके। दुपट्टे की लंबाई भी व्यावहारिक रखनी चाहिए ताकि उसे संभालना आसान रहे।

आभूषणों का चयन भी मौसम को ध्यान में रखकर करना चाहिए। बहुत भारी गहनों की बजाय हल्के लेकिन आकर्षक आभूषण पहनना अधिक आरामदायक रहता है। हीरे, मोती, क्रिस्टल या कुंदन की हल्की कढ़ाई और ज्वेलरी मानसून में सुंदर भी लगती है और नमी का प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है।

फुटवियर का चुनाव अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि मानसून वेडिंग में यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि शादी खुले लॉन या गार्डन में हो रही हो तो ऊंची हील पहनना जोखिम भरा हो सकता है। कीचड़ या गीली घास पर चलने में फिसलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में स्टाइलिश पंजाबी जूती, वेज हील्स या मजबूत ग्रिप वाले आरामदायक फुटवियर बेहतर विकल्प होते हैं। ये न केवल सुरक्षित रहते हैं बल्कि लंबे समय तक पहनने में भी सुविधा देते हैं।

दुल्हन के साथ-साथ शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को भी मानसून के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। अपने साथ एक सुंदर छाता, हल्का स्टोल, अतिरिक्त रूमाल, ब्लॉटिंग पेपर, मिनी मेकअप किट और टिश्यू रखना उपयोगी रहता है। इससे अचानक बारिश या नमी की स्थिति में मेकअप और लुक को आसानी से ठीक किया जा सकता है। मानसून वेडिंग का सबसे बड़ा आकर्षण उसका प्राकृतिक सौंदर्य होता है। हरियाली, बादलों से ढका आसमान और बारिश की हल्की फुहारें शादी की तस्वीरों को भी बेहद खूबसूरत बना देती हैं। यदि थोड़ी-सी योजना, सही ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उपयुक्त परिधान और मौसम के अनुरूप स्टाइलिंग अपनाई जाए तो बारिश का मौसम किसी भी दुल्हन के लिए परेशानी नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती को और भी यादगार बनाने वाला अवसर बन सकता है। सही तैयारी के साथ मानसून की शादी रोमांस, ताजगी, आकर्षण और यादगार पलों का ऐसा संगम बन जाती है, जिसे जीवनभर संजोकर रखा जा सकता है।

— शहनाज़ हुसैन
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ एवं हर्बल क्वीन

केन्द्र सरकार की रिपोर्ट में गुजरात देशभर में अग्रसर

प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▸▸ वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2023 में टीबी के नए मरीजों में 34 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 37 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी

▸▸ वर्ष 2025 में 'स्टेट्स विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट' श्रेणी में गुजरात पूरे देश में प्रथम

▸▸ देश में सबसे कम टीबी के मामले वाले राज्यों में गुजरात छठे तथा बड़े राज्यों में चौथा स्थान प्राप्त किया

▸▸ 'नि-क्षय पोषण योजना' अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1,05,238 टीबी मरीजों को 57.60 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता

▸▸ वर्ष 2025 में राज्य में 3,971 ग्राम पंचायतों ने 'टीबी मुक्त पंचायत' का दर्जा प्राप्त किया

गांधीनगर : कैबिनट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2023 में गुजरात में टीबी के नए मरीजों की दर में 34 प्रतिशत तथा टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुजरात ने वर्ष 2025 में 'स्टेट्स विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट' श्रेणी में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी 'टीबी मुक्त भारत अभियान' अंतर्गत गुजरात राज्य द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रवक्ता मंत्री ने इस संबंध में आगे कहा कि भारत सरकार की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान गुजरात में टीबी के नए मरीजों की अनुमानित दर प्रति एक लाख आबादी पर 186 दर्ज की गई है। इसके आधार पर गुजरात ने देश में सबसे कम टीबी बोझ वाले राज्यों में छठा तथा बड़े राज्यों में चौथा स्थान प्राप्त किया है।

चालू वर्ष के कामकाज का विवरण देते हुए प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि जनवरी से मई–2026 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रो रेटा के अनुसार निर्धारित 58,333 के लक्ष्य के मुकाबले राज्य में 57,334 अर्थात 98.30 प्रतिशत टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें उपचार के अंतर्गत लिया गया। इनमें से 50,928 यानी 91 प्रतिशत मरीज अल्पावधि में ही रोगमुक्त हो गए। इसके अतिरिक्त; भारत सरकार द्वारा 24 मार्च 2026 से प्रारंभ किए गए 'टीबी मुक्त भारत अभियान – 100 दिवस अभियान' अंतर्गत राज्य के 5,012 उच्च जोखिम वाले गांवों में घर-घर जाकर टीबी सर्विलांस किया गया।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान 23.38 लाख व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग, 15.04 लाख व्यक्तियों की एक्स-रे जांच, 5.05 लाख व्यक्तियों की सटीक एनएएटी जांच तथा 32,377 नए टीबी मरीजों का निदान कर उनका उपचार शुरू किया गया है।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि नि-क्षय पोषण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1,05,238 टीबी मरीजों को 57.60 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाएं, कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा स्वैच्छिक संस्थाएं निक्षय मित्र के रूप में जुड़ी हैं। राज्य में अब तक 30,992 नि-क्षय मित्र पंजीकृत हुए हैं, जिन्होंने मरीजों को 5,50,184 पोषण किटों का वितरण किया है।

वर्ष 2025 के दौरान राज्य की 3,971 ग्राम पंचायतों ने 'टीबी मुक्त पंचायत' का दर्जा प्राप्त किया, जो राज्य की कुल ग्राम पंचायतों का लगभग 27 प्रतिशत है।

मानसून के दौरान महेसाणा-तारंगा हिल रेलखंड पर तीन रेलवे अंडरपास अस्थायी रूप से रहेंगे बंद

यात्रियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद मण्डल द्वारा महेसाणा–तारंगा हिल रेलखंड पर स्थित तीन रेलवे अंडरपास (RUB) को मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा होने की स्थिति में 10 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है—

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 41A – वडनगर सिटी के समीप (केसिंपा खेतों का मार्ग विस्तार)

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 16D – विसनगर सिटी के समीप (शेरडीनगर से कांसा विस्तार)

रेलवे अंडरपास (RUB) संख्या 22A – मस्तान नगर सोसायटी, वडनगर दरवाजा अहमदाबाद मण्डल आम नागरिकों से अनुरोध करता है कि इस अवधि में रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें तथा भारी वर्षा के दौरान इन रेलवे अंडरपासों का उपयोग करने से बचें।

बच्चों के स्वस्थ-सुरक्षित भविष्य की दिशा में गुजरात सरकार की अनूठी पहल, राज्य में 18 साल तक के हर बच्चे का बनेगा 'हेल्थ पासपोर्ट'

▸▸ 992 मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा हर साल 1.89 करोड़ बच्चों (0-18 वर्ष) का चेकअप कर तैयार किया जाएगा 'हेल्थ पासपोर्ट'

▸▸ जन्म से 18 साल तक की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, बीमारियों (4D) की ट्रैकिंग और पोषण का स्तर अब एक ही डॉक्युमेंट में

▸▸ 5 साल तक व स्कूल न जाने वाले बच्चों का कार्ड PHC मेडिकल ऑफिसर, जबकि छात्रों का कार्ड स्कूल प्रिंसिपल करेंगे रिन्यू

वडोदरा, 01 जुलाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात पर ज़ोर देते हैं कि एक 'स्वस्थ भारत' की मजबूत नींव, 'स्वस्थ बचपन' पर ही रखी जा सकती है। पीएम मोदी के इसी विजन को धरातल पर उतारते हुए और 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों व किशोर-किशोरियों की हेल्थकेयर सुविधाओं को और ज्यादा स्मार्ट, सस्टेनेबल और फैमिली एवं चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए 'हेल्थ पासपोर्ट' का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। स्कूल हेल्थ - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SH-RBSK) के तहत अब गुजरात में जन्म से 18 साल तक के हर बच्चे का अपना एक हेल्थ पासपोर्ट होगा। यह सिर्फ कोई सामान्य हेल्थ कार्ड नहीं, बल्कि बच्चे की जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की पूरी स्वास्थ्य यात्रा का एक पक्का डॉक्युमेंट होगा। उल्लेखनीय है कि इस राज्यव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत 27 जून 2026 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में की गई है।

1.89 करोड़ बच्चों के पास होगा अपना 'हेल्थ पासपोर्ट', 992 मोबाइल टीमें करेंगी तैयार

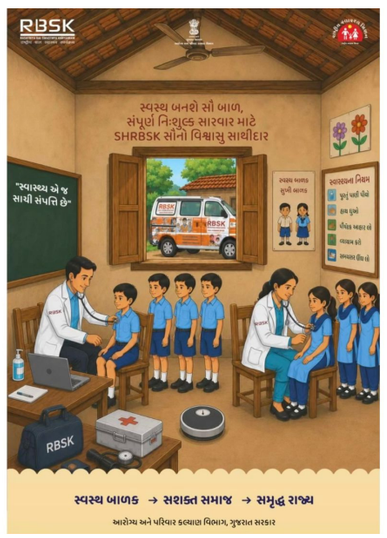

गुजरात में SH-RBSK के तहत हर साल लगभग 1.89 करोड़ बच्चों का हेल्थ चेकअप 992 मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा किया जाता है। फिलहाल इन चेकअप्स का रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर तो मौजूद है, लेकिन माता-पिता या बच्चों के पास ऐसा कोई हैंडी डॉक्युमेंट नहीं होता, जिसे वे रेगुलर रूटीन चेकअप, इलाज या फॉलो-अप के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकें। प्रस्तावित 'हेल्थ पासपोर्ट' इसी कमी को दूर करेगा और बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमैटिक और आसान फॉर्मैट में पेश करेगा।

आसान होगी हेल्थ पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, स्क्रीनिंग स्थल पर ही मिलेगा पासपोर्ट, कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं

अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। बच्चों का 'हेल्थ पासपोर्ट' बनवाने के लिए माता-पिता को कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। SH-RBSK की मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा आंगनवाड़ी, स्कूल, मदरसा, गुरुकुल और स्पेशल स्कूलों में बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग और डिजिटल प्लैटफॉर्म पर डेटा एंट्री के बाद बच्चों को यह हेल्थ पासपोर्ट वहीं दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके रिन्यूअल की व्यवस्था भी स्पष्ट है। 5 साल तक के बच्चों या स्कूल न जाने वाले बच्चों के हेल्थ पासपोर्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के मेडिकल ऑफिसर (MO) द्वारा हर साल रिन्यू किया जाएगा। वहीं, स्कूली छात्रों के लिए यह जिम्मेदारी स्कूल के प्राचार्य निभाएँगे।

18 साल तक के बच्चों की पूरी हेल्थ हिस्ट्री का 'इन्टीग्रेटेड रिकॉर्ड' बनेगा गुजरात का 'हेल्थ पासपोर्ट'

यह हेल्थ पासपोर्ट हर बच्चे की पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री का एक मास्टर डॉक्युमेंट होगा। इसमें बच्चे की बेसिक डिटेल्स के साथ जन्म से 18 साल तक के उम्र-वार हेल्थ चेकअप का पूरा रिकॉर्ड दर्ज रहेगा। इसके अलावा, स्कूल हेल्थ-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SH-RBSK) के तहत फोकस की जाने वाली चार प्रमुख कैटेगरीज (4D) यानी जन्मजात डिफेक्ट्स, बीमारियां, न्यूट्रिशन की कमी और डेवलपमेंट में देरी या विकलांगता का पूरा अपडेट इसमें शामिल होगा। यही नहीं, बच्चे की शारीरिक-मानसिक वृद्धि व विकास, पोषण का स्तर, रेफरल सर्विसेज, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स, लाइफस्टाइल एडवाइस और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी इस पासपोर्ट का हिस्सा होंगे। आसान शब्दों में कहें तो परिवारों को बच्चे की सेहत से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी।

इस पहल की सबसे बड़ी यूएसपी इसका डिजिटल इंटीग्रेशन है। हेल्थ पासपोर्ट की फिजिकल कॉपी माता-पिता के पास ही सुरक्षित रहेगी, लेकिन इसे SH-RBSK डिजिटल पोर्टल के साथ पूरी तरह से सिंक किया जाएगा, जिससे डेटा मैनेजमेंट बिल्कुल सीमलेस रहेगा। अगर किसी वजह से फिजिकल हेल्थ पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो नया हेल्थ पासपोर्ट मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। गुजरात सरकार द्वारा बच्चों के लिए लाए जा रहे इस 'हेल्थ पासपोर्ट' का मकसद सिर्फ मेडिकल फाइलें तैयार करना नहीं है, बल्कि माता-पिता को बच्चों के हेल्थ मैनेजमेंट में एक एक्टिव पार्टनर बनाना है। इससे बच्चों, पैरेंट्स और हेल्थकेयर सिस्टम के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनेगा।